*114. [The *questioner (Shri. Ram Avadesh Singh) was absent. For answer,* vide col. 44-48 infra]

Shortage of power in southern zone

*115. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Southern Zone is still having an estimated deficiency of 18. 8 per cent in the availability of power;

(b) if so, what steps are being contemplated by Government to meet the situation;

(c) whether there is any proposal for building a gas grid covering the Southern State from Bombay to increase power production in the South; and

(d) if so, what are the details thereof?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबनराव धाकने) : (क) अप्रैल, 1990 से जनवरी, 1991 की अवधि के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी 10.6 प्रतिशत थी ।

(ख) विद्युत की उपलब्धता में सुधार किये जाने के लिये किये जा रहे उपायों में ये शामिल हैं, नई विद्युत उत्पादन क्षमता चालू करना, अपावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, पारेषण और वितरण संबंधी हानियों की मात्रा में कटौती करना, मांग प्रबंध तथा ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को क्रियान्वित करना तथा ऐसे क्षेत्र जिनमें ऊर्जा अधिशेष होती है, इन क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों में ऊर्जा अन्तरण का प्रबन्ध करना ।

(ग) और (घ) पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में पाइप लाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की ढुलाई के लिये पाइपलाइन का निर्माण किये जाने से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिये पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा मई, 1990 में एक अन्तःमंत्रालय दल का गठन किया गया था । रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है ।

SHRI E. BALANANDAN: Sir, question about power deficiency in the Southern area has been there since long and only the usual answer is given. The usual steps that have been suggested to be taken by the Government have been a regular feature which is given everywhere and every-time. The country's development mainly hinges on power. But power supply in certain areas has been zero a complete zero. Therefore, this aspect as to be taken care of by the Government. In part (b) of the answer, some small steps are proposed to be taken by the Government. I want to ask one question with regard to power development. For power generation and power development today we are using coal, hydel and other sources. The Ministry of Energy says that proportion of hydel power is coming down, and the Government is trying to tap only the costly sources. At the same time they say there is financial stringency everywhere. But the Government is not giving clearance to low-cost projects. Such projects are not being given the requisite priority by the Government. Therefore, my question in that regard is, keeping in view the power deficiency in the State of Kerala, and keeping in view the projects awaiting clearance from the Government, will the Government of India take steps to see that projects like the Pooyankutty Project, are/ immediately given clearance?

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय सभापति महोदय, जहां तक केरल के अन्दर विद्युत सप्लाई की कमी की बात है माननीय सदस्य को मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि केरल में अभी विद्युत सप्लाई की कोई कमी नहीं है । हमारे यहां पर आपने सदर्न जोन में जो विद्युत कमी की बात कही थी वह 18.8

प्रतिशत कही थी तो वह 18.8 प्रतिशत नहीं हो करके 10.7 प्रतिशत है। अभी सदर्न जोन के दूसरे राज्यो के अन्दर जिस तरह की कमी है वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में 7.8 प्रतिशत है, कर्नाटक में 20.9 प्रतिशत है, तथमलनाडु में 9.1 प्रतिशत है और कुल मिला कर औसत 10.9 प्रतिशत आता है।

श्री सभापति : केरल में कोई कमी नहीं है ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : नहीं।

SHRI E. BALANANDAN: The lion. Minister says there is n_0 deficiency of power in Kerala. But If come from Kerala and I know there is deficiency and we are somehow adjusting this shortage. It is more than the average of 10. 6 mentioned by the Minister. But taking an average in such cases is not an indication of the true picture. My question was, to relieve Kerala of this difficulty, and in view of the financial stringency being faced by the Government, will the Government of India give preference and accord clearance to pending projects, especially the project called Pooyankutty project, which has been pending for years, and give clearance immediate-
ly.

MR. CHAIRMAN: He is asking about a particular project.

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय सदस्य को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सदर्न जोन के अन्दर विद्युत सप्लाई की जो कमी है, उसकी पूर्ति के लिये केन्द्रीय क्षेत्र से उनको बिजली देने की व्यवस्था कर रखी है। हम आंध्र को रामागुंडम से 1580 मेगावाट दे रहे हैं, कर्नाटक को 345 दे रहे हैं, केरल को 245 दे रहे हैं, तमिलनाडु को 470 दे रहे हैं, और पांडिचेरी को 50 मेगावट दे रहे हैं उसी तरह से नैवेलि लिग्नाइट कार्पो० से हम आंध्र को 97 मेगावाट दे रहे हैं। उसी तरह से कल्पकम् से हम 40;30;25 और 350 मेगावाट क्रमश: दे रहे हैं ताकि उनकी बढ़ती हुई मांग की पूर्ति की जा सके। उसी तरह से सेंटर का जो अन-एलोकेटेट कोटा है उसके अन्दर भी हम बिजली देकर उनकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सभापति : उनका प्रश्न एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में है।

SHRI B. BALANANDAN: He did not answer the question as to what has to be done.

MR. CHAIRMAN: You name the project again.

SHRI E. BALANANDAN: I once again invite the attention of the Minister that a project named as Pooyankutty Hydel Project is there pending clearance with the Central Government for years together. The latest information which I had received from the Minister is that it will be cleared within three months. Can you give us the assurances that this clear ance will be given expeditiously, at the latest, within a month?

श्री कल्याण सिंह कालवी : इसको अति शीघ्र अनुमति देने की कोशिश कर रहे हैं ?

SHRI E. BALANANDAN: Regarding parts (c) & (d) of my question about the gas project it is stated that a Committee is going on and is considering the pipeline transportation etc.

MR. CHAIRMAN: He had answered already.

SHRI E. BALANANDAN: What We want is the time-frame. Committees are a device to postpone anything on earth. Therefore, I want to know from the Government as to what is the time-frame set by the Committee? When will the report be ready? Will the Government take serious steps to

see that immediately the report is go and action is taken.

श्री कल्याण सिंह कालखी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि साउथ जोन के बारे में कमेटी बना चुके हैं । वह कमेटी विचार कर रही है । फरवरी में उसकी बैठक हुई है । उसकी रिपोर्ट आने के बाद अतिशीघ्र कार्यान्वयन किया जायेगा । आपने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जो एक बात कही थी, मैं एक विशेष जानकारी दे देना चाहता हूं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर जितने भी दक्षिण के राज्य हैं, उनको समुद्र से जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि जहाज के जरिए कोयला सप्लाई करके वहां पर थर्मल स्टेशंस ज्यादा-से-ज्यादा स्थापित किए जा सकें और कोयले की पूर्ति की कमी न रहने दी जाय । इस तरह की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं । उसी के साथ-साथ जहाज की अपने आप लोडिंग हो, अन-लोडिंग हो इस तरह की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं ताकि किसी तरह की कमी न हो और आप जिस बात से चिंतित हैं कि सदर्न जोन के अन्दर बिजली की कमी आने वाले समय में लोगों को परेशान करेगी, उस परेशानी से हम आपको मुक्त कर देंगे ।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Sir, I am informed that other zones are havng a surplus of 15 per cent. In view of the shortage of power in Andhra Pradesh, the Andhra Pradesh Government has requested the Centre to allot a part of the surplus to Andhra Pradesh. The surplus is there with NTPC. The NTPC has to concerned the demand. I request the hon. Minister to give a positive reply. Now 4 hours cut in electricity is there in the urban areas.

SHRI PARVATHANENI UPEND-RA: NTPC has a reserve of 15 per cent. The question is whether you will allocate that 15 per cent to Andhra Pradesh.

श्री कल्याण सिंह कालखी : जैसा कि मैंने कहा था आंध्र प्रदेश में जो बिजली की कमी है, उसमें सेंटर का जो अन-एलोकेटेड कोटा है, उसमें से 25 प्रतिशत बिजली आंध्र को दे रहे हैं ।

SHRI A. K. ANTONY: While replying to the question raised by Mr. Balanandan, the hon. Minister said that, as far as Kerala is concerned, there is no power shortage. But coming from Kerala, we know what is the real position. We are facing acute power shortage. There is frequent power cut. Therefore, I would like to know from the hon. Mnister, which is the source which has given this wrong information to him that there is no power shortage in Kerala? I would request the hon. Minister to correct this source. I would also request him to give us a specific time-limit for the clearance of the Pooyan-kutty project, which is highly important, as far as Kerala is concerned.

MR. CHAIRMAN: Now, two Members, one from this side and one from the other side, have said that there is power shortage in Kerala.

श्री कल्याण सिंह कालखी : सभापति महोदय, जैसा मैंने बताया, एक ही स्रोत है, जो हमारा विभाग है.. (व्यवधान)

श्री सभापति : इसको आप देख लीजिए कि गलत खबर है या सही खबर है और इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी मंजूरी दी जाय, यह सब तरफ से एक ही आवाज, एक ही बात उठी है ।

श्री राजमंगल पाण्डेय : इन्होंने कह दिया कि मंजूरी जल्दी हो जायेगी ।

श्री कल्याण सिंह कालखी: मैंने कहा कि अतिशीघ्र हो जायेगी ।

SHRI S, JAIPAL REDDY: Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Energy to the question raised by my friends, Mr. Hanumantha Rao and Mr. Upendra, which was not answered. Therefore,

I am obliged to repeat it. The question put was this. There is the Ramagun-dam super thermal power station, which is under the N. T. P. C. Fifteen per cent of the energy is there as reserve. This has not been made available to any State in the country. 1 therefore, would like to know from the hon. Minister whether this reserve power will be diverted, on a temporary basis, *to* the State of Andhra Pradesh, which is suffering from power deficiency. Did I make myself understand, Mr. Minister?

श्री सभापति : वह यह कह रहे हैं कि रामागुंडम में एन.टी.पी.सी. की जो रिजर्वड रखी हुई है, इसके अलावा दे रहे हैं क्या?

श्री कल्याण सिंह कालवी : इसमें जो 15 परसेंट का सेंटर का कोटा है, उस बिजली को जिस तरह से सदर्न जोन में बांटा जा रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कि आंध्र प्रदेश को हम 25 प्रतिशत उसमें से बिजली दे रहे हैं, कर्नाटक को 33 प्रतिशत दे रहे हैं, केरल को 15 प्रतिशत दे रहे हैं ।

MR. CHAIRMAN: The extra is being distributed. (*Interruptions)*

SHRI S. JAIPAL RUDDY: He is referring to the distribution of power. I am referring to the reserve power.

MR, CHAIRMAN; He said that the reserve is being distributed.

SHRI S. JAIPAL REDDY: No.

SHRI PARVATHANKNI UPEND-RA: He is giving the figures in regard to the distribution from the total power.

SHRI S. JAIPAL REDDY: He has not understood the question. In regard to the total power produced, his answer is correct. But I am drawing his attention to the reserve power, which is to the tune of 15 per cent. Will that be diverted to Andhra Pradesh, on a temporary basis?

श्री कल्याण सिंह कालवी : सभापित महोदय, जो 15 परसेंट सेंटर के पास अनएलोकेटेड कोटा रहता है, उसी में से से इस तरह मैंने बताया ।

श्री सभापति : वह तो रामागुंडम के रिजर्व का आपसे पूछ रहे हैं, जो उनके पास रिजर्व है ।

श्री कल्याण सिंह कालवी : उसी में से दे रहे हैं ।

MR, CHAIRMAN: I was correct.

SHRI PARVATHANENI UPEND-RA: It is one-fourth of the 15 per cent.

श्री कल्याण सिंह कालवी : उस 15 प्रतिशत को जिस तरह से बांटा है, यह मैंने आपको बताया है ।

*116/ *[The questioner Prof. Sou-For answer vide col* 47 *infra], rendra Bhattacharjee) was absent*

तेल शोधक कारखानों में तेल की हानि को कम करने के उपाय

*117. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह : अरोड़ा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तेल शोधक कारखानों में तेल शोधन की प्रक्रिया में तेल की 7 प्रतिशत हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अन्य देशों के तेल शोधक कारखानों में तेल की कितनी हानि होती है ;

t The question was actually asked on the floor of the Hous$_e$ by Sardar Jagjit Singh Aurora.